

Think
IAS...



Think
Drishti

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

आधुनिक भारत

(बिहार के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-2

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: BRPM07



बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

आधुनिक भारत

(बिहार के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-2



641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष : 011-47532596, 8750187501

टोल फ्री : 1800-121-6260

Web : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें



www.facebook.com/drishtithevisionfoundation



www.twitter.com/drishtiiias

9. राष्ट्रवाद का उदय	5-19
9.1 भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण	5
9.2 कॉन्ग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएँ	8
9.3 भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस की स्थापना	11
10. राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण	20-37
10.1 उदारवादी चरण	20
10.2 उग्रवादी चरण	22
10.3 बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन	24
10.4 क्रांतिकारी आंदोलन (प्रथम चरण)	29
11. राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण	38-72
11.1 होमरूल आंदोलन	38
11.2 गांधीवादी आंदोलन (प्रथम चरण)	40
11.3 क्रांतिकारी आंदोलन (द्वितीय चरण)	46
11.4 भारत में दलित आंदोलन	48
11.5 गांधीवादी आंदोलन (द्वितीय चरण)	49
12. राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों एवं महिलाओं की सहभागिता	73-86
12.1 ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन	73
12.2 राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता	74
12.3 विविध	76
13. गणतंत्र के रूप में भारत का उदय	87-92
13.1 राज्यों का पुनर्गठन	87
13.2 बिहार का गठन	89
13.3 झारखंड के पृथक्करण के बाद बिहार	90

14. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के प्रमुख घटनाक्रम	93–105
14.1 राष्ट्र का विभाजन	93
14.2 रियासतों का एकीकरण	94
14.3 सांप्रदायिक हिंसा	98
14.4 शरणार्थियों की समस्या	99
14.5 जे.पी. आंदोलन और आपातकाल	100
15. वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति	106–123
15.1 भारत की विदेश नीति और पंचशील समझौता	106
15.2 निर्गुट आंदोलन	114
15.3 भारत-चीन युद्ध	114
15.4 भारत-पाकिस्तान युद्ध	119
15.5 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन	119
15.6 संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत	120

राष्ट्रवाद कोई अचानक उत्पन्न होने वाली विचारधारा नहीं है बल्कि यह एक दीर्घकालिक विकासशील प्रक्रिया है। राष्ट्र के लिये एक ऐसी भावना का होना आवश्यक है जो व्यक्तियों के समूह को आत्मिक रूप से जोड़ती है और जब राष्ट्र व्यक्ति की पहचान बन जाता है तो राष्ट्रीयता जन्म लेती है और जब राष्ट्रीयता एक विचारधारा का रूप ले लेती है, तब राष्ट्रवाद का उदय होता है। यही विचारधारा **राष्ट्रीय आंदोलन** या **स्वतंत्रता आंदोलन** की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारक बनता है।

कुछ इतिहासकार भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति को **प्रेरण-अनुक्रियावाद** से स्पष्ट करते हैं जिसका आशय है- ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों के लिये भारत में जो व्यवस्थाएँ लागू कीं, भारतीयों ने उसी पर अनुक्रिया कर राष्ट्रवादी भावना को विकसित किया। उल्लेखनीय है कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति एक आधुनिक संकल्पना मानी जाती है। भारत में जैसे-जैसे औपनिवेशिक शासन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा, वैसे-वैसे **भारतीय राष्ट्रवाद** भी विकसित होता गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसी समय **दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** की स्थापना हुई, जिसके नेतृत्व में भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया और अंततः 15 अगस्त, 1947 को देश को ब्रिटिश दासता से मुक्ति मिली।

9.1 भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण (Causes of Rise of Indian Nationalism)

भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अथवा राष्ट्रवाद का उदय अनेक कारणों तथा परिस्थितियों का परिणाम था, जिन्हें निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-

विदेशी आधिपत्य (Foreign mastery)

- आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उभरा। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता की।
- राष्ट्रवाद की जड़ें भारतीय जनता के हितों तथा भारत में ब्रिटिश हितों के टकराव में थीं। भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग ने यह अनुभव किया कि लंकाशायर के उद्योगपतियों तथा अंग्रेजों के दूसरे प्रमुख वर्गों के हितों के लिये उनके अपने हितों का बलिदान दिया जाता है।
- किसान अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भू-राजस्व के रूप में देने से असंतुष्ट थे तथा जब कभी किसान जमींदारों और सूदखोरों के दमन के खिलाफ विद्रोह करते, तब पुलिस तथा सेना कानून व्यवस्था के नाम पर उनको कुचल दिया करती थी।
- दस्तकार और शिल्पी वर्ग ने यह महसूस किया कि सरकार विदेशी प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर उनको तबाह कर रही थी तथा उनके पुनर्वास के लिये कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था।
- 20वीं शताब्दी में आधुनिक कारखानों, खदानों तथा बागानों के मजदूरों ने जब कभी **मजदूर ट्रेड यूनियन**, हड़ताल, प्रदर्शन तथा संघर्ष आदि के द्वारा स्वयं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, तब सरकार का पूरा तंत्र उनके खिलाफ उठ खड़ा होता था।
- समाज के कई वर्गों ने यह भली-भाँति समझ लिया था कि बढ़ती बेरोजगारी का समाधान केवल तीव्र औद्योगीकरण से संभव है जो एक स्वाधीन सरकार द्वारा किया जा सकता है।
- स्वयं ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बनता गया और यह भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्त्व बन चुका था।

परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (दिसंबर 1885) के समय लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी।
- दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था।
- कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना 1884 ई. में ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की सामाजिक समस्याओं के संबंध में विचार-विमर्श करना था।
- लैंड होल्डर्स सोसायटी (1838 ई.) पहली सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिये संवैधानिक उपायों का प्रयोग किया।
- सेप्टी वॉल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक 'यंग इंडिया' में 1916 ई. में प्रस्तुत किया।
- सर पी.सी. इल्बर्ट, जो कि वायसराय की परिषद में विधि सदस्य थे, ने 1883 ई. में एक बिल पेश किया जिसका उद्देश्य था- 'जातिभेद पर आधारित न्यायिक अयोग्यताएँ' समाप्त की जाएँ। इस बिल से विवाद उत्पन्न हो गया जो 'इल्बर्ट-विवाद' के नाम से जाना जाता है।
- 1939 ई. में त्रिपुरी के कांग्रेस सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस के बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया।
- स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे, जबकि 1948 ई. में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभि सीतारमैया थे।
- 1923 ई. में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन (दिल्ली) में अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष रहे।
- कांग्रेस द्वारा असहयोग के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में स्वीकार किया गया।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी-

60-62वीं, B.P.S.C. (Pre)

- (a) ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन
(b) इंडियन एसोसिएशन
(c) इंडियन नेशनल यूनियन
(d) इंडियन लीग
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

2. इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? 56-59वीं, B.P.S.C. (Pre)

- (a) श्रीमती एनी बेसेंट (b) सुचेता कृपलानी
(c) सरोजिनी नायडू (d) इंदिरा गांधी

3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 53-55वीं, B.P.S.C. (Pre)

- (a) 52 (b) 62
(c) 72 (d) 82

4. राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी?

48-52वीं, B.P.S.C. (Pre)

- (a) बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी
(b) ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
(c) यंग बंगाल एसोसिएशन
(d) इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता

5. किसने कहा था, "कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था।?" 47वीं, B.P.S.C. (Pre)

- (a) लॉर्ड डफरिन (b) सर सैय्यद अहमद खाँ
(c) लॉर्ड कर्जन (d) लाला लाजपत राय

6. वह कौन-सा कांग्रेस अध्यक्ष था, जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से बातें की?

47वीं, B.P.S.C. (Pre)

- (a) अबुल कलाम आजाद (b) जवाहरलाल नेहरू
(c) जे.बी. कृपलानी (d) सी. राजगोपालाचारी

7. अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ई. में सत्ता हस्तांतरित किये जाने के समय कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
46वीं, B.P.S.C. (Pre)
- (a) जवाहरलाल नेहरू
(b) राजेंद्र प्रसाद
(c) अबुल कलाम आज़ाद
(d) जे.बी. कृपलानी
8. सन् 1930 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस समिति को गैर-कानूनी करार दे दिया गया था, यह आदेश है-
46वीं, B.P.S.C. (Pre)
- (a) गैर-कानूनी संधि अध्यादेश
(b) शांति कानून का उल्लंघन
(c) कार्यपालक अधिकार अध्यादेश
(d) वायसराय का विशेष आदेश
9. भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की?
45वीं, B.P.S.C. (Pre)
- (a) गणेश अगरकर (b) सुरेंद्रनाथ बनर्जी
(c) दादाभाई नौरोजी (d) फिरोजशाह मेहता
10. निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ई. में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी?
44वीं, B.P.S.C. (Pre)
- (a) बाल गंगाधर तिलक (b) गोपाल कृष्ण गोखले
(c) अरविन्द घोष (d) दादाभाई नौरोजी
11. भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस की स्थापना की थी-
44वीं, B.P.S.C. (Pre)
- (a) ए.ओ. ह्यूम ने (b) महात्मा गांधी ने
(c) एनी बेसेंट ने (d) लाला लाजपत राय ने
12. भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
44वीं, B.P.S.C. (Pre)
- (a) दिल्ली में (b) लाहौर में
(c) मुंबई में (d) पटना में
13. भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस की स्थापना की गई-
43वीं, B.P.S.C. (Pre)
- (a) 1865 में (b) 1867 में
(c) 1885 में (d) 1887 में
14. भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के संस्थापक एक-
43वीं, B.P.S.C. (Pre)
- (a) असैनिक सेवक (b) विज्ञानी
(c) सामाजिक कार्यकर्ता (d) मिलिट्री कमांडर
15. 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए-
41वीं, B.P.S.C. (Pre)
- (a) अबुल कलाम आज़ाद
(b) सुभाषचंद्र बोस
(c) पट्टाभि सीतारमैया
(d) जे.बी. कृपलानी
16. भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएँ-
41वीं, B.P.S.C. (Pre)
- (a) सरोजिनी नायडू (b) पंडिता रमाबाई
(c) अरुणा आसफ अली (d) एनी बेसेंट
17. कॉन्ग्रेस पार्टी ने किस वर्ष 'पूर्ण स्वराज' का प्रस्ताव पारित किया?
38वीं, B.P.S.C. (Pre)
- (a) 1926 में (b) 1929 में
(c) 1917 में (d) 1911 में
18. भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस में विभाजन हुआ, सूरत अधिवेशन में-
(a) 1905 में (b) 1907 में
(c) 1909 में (d) 1910 में
19. भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया-
(a) लाहौर अधिवेशन में (b) अमृतसर अधिवेशन में
(c) बंबई अधिवेशन में (d) कराची अधिवेशन में
20. भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी-
(a) एनी बेसेंट ने
(b) लोकमान्य तिलक ने
(c) संपूर्णानंद ने
(d) अंबिका चरण मजूमदार ने
21. लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी-
(a) रामकृष्ण मिशन की स्थापना
(b) ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना
(c) भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस की स्थापना
(d) प्रथम जनगणना की शुरुआत
22. इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था?
(a) जवाहरलाल नेहरू (b) अबुल कलाम आज़ाद
(c) आनंद मोहन बोस (d) भूपेंद्र नाथ बोस

23. भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिये निम्नलिखित में से किन कारकों ने योगदान दिया?
1. पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन से संपर्क
 2. रेलवे का विकास
 3. समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेख
 4. इल्बर्ट विवाद
- कूट:**
- (a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 2 तथा 4
(c) केवल 1 तथा 3 (d) सभी
24. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में सुरक्षा कपाट सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
- (a) बाल गंगाधर तिलक (b) लॉर्ड डफरिन
(c) लाला लाजपत राय (d) विपिन चंद्र पाल
25. अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात् इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया?
- (a) अबुल कलाम आजाद (b) राजेंद्र प्रसाद
(c) पट्टाभि सीतारमैया (d) वल्लभभाई पटेल
26. पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था?
1. राधाकांत देव
 2. एम.जी. रानाडे
 3. गणेश वासुदेव जोशी
 4. फिरोजशाह मेहता
- कूट:**
- (a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 2 तथा 4
(c) केवल 2 तथा 3 (d) 1, 2, 3 और 4
27. 'भारत छोड़ो आंदोलन' का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया?
- (a) लाहौर (b) बंबई
(c) कलकत्ता (d) अहमदाबाद
28. मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई?
- (a) आनंदमोहन बोस (b) शिशिर कुमार बोस
(c) एम. वीर राघवाचारी (d) फिरोजशाह मेहता
29. 'इंडियन एसोसिएशन' की स्थापना किस वर्ष की गई?
- (a) 1884 ई. (b) 1875 ई.
(c) 1876 ई. (d) 1888 ई.
30. कांग्रेस द्वारा 'असहयोग आंदोलन' के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 ई. में किस स्थान पर स्वीकार किया गया था?
- (a) कलकत्ता (b) नागपुर
(c) बनारस (d) गया
31. कौन-सा नेता था जो लगातार छः वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा?
- (a) दादाभाई नौरोजी (b) जवाहरलाल नेहरू
(c) अबुल कलाम आजाद (d) राजेंद्र प्रसाद
32. गांधीजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी?
- (a) लखनऊ, 1916 (b) अमृतसर, 1919
(c) बेलगाँव, 1924 (d) कलकत्ता, 1928

उत्तरमाला

- | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (b) | 2. (c) | 3. (c) | 4. (d) | 5. (b) | 6. (a) | 7. (d) | 8. (a) | 9. (c) | 10. (d) |
| 11. (a) | 12. (c) | 13. (c) | 14. (a) | 15. (b) | 16. (d) | 17. (b) | 18. (b) | 19. (a) | 20. (d) |
| 21. (c) | 22. (b) | 23. (d) | 24. (c) | 25. (b) | 26. (c) | 27. (b) | 28. (c) | 29. (c) | 30. (a) |
| 31. (c) | 32. (c) | | | | | | | | |

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. उन कारकों का वर्णन कीजिये, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता की।
2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों को स्पष्ट करें। इसके वास्तविक उद्देश्य क्या थे?
3. अंग्रेजों की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियों ने किस प्रकार राष्ट्रवाद को प्रेरित किया? स्पष्ट कीजिये।
4. कांग्रेस की स्थापना से पूर्व उन महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन करें, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्फूर्ति प्रदान किया।
5. क्या आप मानते हैं कि इल्बर्ट बिल विधेयक ने भारतीय राष्ट्रवाद को उभारने में मदद की? इस परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड लिटन एवं कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीतियों का वर्णन करें।

राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण
(First Phase of National Movement)

भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश रहा है। ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीतियों तथा ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति हेतु उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और एक संगठित आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय इतिहास में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबे समय तक चलने वाले इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यद्यपि मई 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष माना जाता है, परंतु इसकी औपचारिक शुरुआत 1885 ई. में कॉंग्रेस की स्थापना के साथ हुई जो कई उतार-चढ़ावों से गुजरते हुए 15 अगस्त, 1947 तक अनवरत रूप से जारी रहा।

यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी का भारत विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र में विभाजित था तथा ब्रिटिश शासकों ने भी इस विभाजन को बनाए रखने के लिये 'फूट डालो और राज करो' की नीति को अपनाया, तथापि भारत एक भौगोलिक इकाई मात्र नहीं था, बल्कि इस विविधता में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक चेतना भी अंतर्निहित थी, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ, विकास एवं सफलता की ओर अग्रसर होने में सहायता प्रदान की। विविधता के मूल में अंतर्निहित यह राष्ट्रीय चेतना ही थी, जिसने राष्ट्रवाद का विकास किया तथा भाषा, धर्म, जाति के बंधन को लौघते हुए लोगों को एक सूत्र में संगठित किया। हालाँकि यह भी सच है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था तथा आधुनिक विचारों के प्रचार-प्रसार ने भी एक सीमा तक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया, लेकिन ब्रिटिश शासन का कभी भी यह उद्देश्य नहीं था कि भारत में राष्ट्रवाद का बीजारोपण हो बल्कि उन्होंने अपने औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही कुछ सुधार किये, जिससे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और वे राष्ट्रीय आंदोलन के लिये प्रेरित हुए।

10.1 उदारवादी चरण (Moderate Phase)

भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के एक नए युग का आरंभ हो गया। चूँकि कॉंग्रेस का शुरुआती नेतृत्व जिन नेताओं ने किया, उनका स्वभाव सरल एवं कार्य-प्रणाली उदार प्रकृति की थी, इसलिये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। कॉंग्रेस के आरंभिक 20 वर्षों के काल को उदारवादी राष्ट्रीयता की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस काल में कॉंग्रेस की नीतियाँ काफी उदार थीं। इस समय कॉंग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का प्रभाव था, जिनमें अधिकतर पत्रकार, वकील, इंजीनियर एवं डॉक्टर इत्यादि प्रमुख थे। ये उदारवादी नेता अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठावान थे तथा उन्हें अपना शत्रु नहीं मानते थे। दादाभाई नौरोजी के इन शब्दों से अंग्रेजों के प्रति उनकी भावनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति का पता चलता है- "हम ब्रिटिश प्रजा हैं, हम अपने हक की मांग कर सकते हैं। अगर हमें ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से वंचित रखा जाता है तो फिर भारत को अंग्रेजों के स्वामित्व में रहने से क्या लाभ? यह तो एक और एशियाई निरंकुश शासन मात्र होगा।"

इस समय के उदारवादी नेताओं में फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रमेशचंद्र दत्त प्रमुख थे। कालांतर में द्वारिकानाथ गांगुली, एम.जी. रानाडे, वीर राघवाचारी, आनंद चारलू और गोपालकृष्ण गोखले भी इसमें शामिल हो गए।

उदारवादियों की कार्य-प्रणाली (Working system of moderates)

उदारवादियों को नरमपंथी के नाम से भी जाना जाता था। उनकी कार्य-प्रणाली एक विशिष्ट तरीके की थी, जिसमें वे अपने प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं उनके द्वारा स्थापित अंग्रेजी राज की प्रशंसा करते थे और अपनी मांगों को उनके पास रखते थे। वे अपनी उन मांगों को समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से स्पष्ट करते थे ताकि जनता पर भी उनके कार्यों का प्रभाव पड़े।

राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण
(Second Phase of National Movement)

भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में उदारवादियों, उग्रवादियों, महिलाओं तथा किसानों एवं मजदूरों ने अपना सर्वस्व योगदान दिया। परिणामस्वरूप निरंतरता एवं परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। परिवर्तन के क्रम में सफलता एवं असफलता निरंतर बनी रही। वस्तुतः आंदोलन का उद्देश्यपूर्ति तुरंत/शीघ्र न होकर जनता के जागृति, स्वतंत्रता के प्रति कर्तव्य, साम्राज्यवाद पर दबाव डालने और उसके लिये सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना तथा आत्म त्याग की भावना का विकास करने से होता है। यदि इस पहलू के आधार पर उदारवादियों एवं क्रांतिकारियों की भूमिका के बारे में विचार करें तो हम पाते हैं कि उन्होंने भारत के युवकों में जागृति फैलाने और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में जुट जाने का आह्वान किया। वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय स्वतंत्रता भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न वैचारिक आयामों से होकर गुजरा।

11.1 होमरूल आंदोलन (Home Rule Movement)

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1916 ई. में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 'अखिल भारतीय होमरूल लीग' की स्थापना की गई। इसी लीग के द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ होमरूल आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होमरूल आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए भारत में इस आंदोलन का सूत्रपात किया था।

इस आंदोलन के तहत स्वशासन के उद्देश्य को महत्त्व देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया और इस आंदोलन में दो अलग-अलग होमरूल लीगों की स्थापना की गई, पहला बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में पूना में तथा दूसरा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में। दोनों होमरूल लीगों ने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारत को होमरूल या स्वराज्य देने की मांग के पक्ष में भारत में जोरदार प्रचार किया। इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने यह लोकप्रिय नारा दिया- "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।"

तिलक की होमरूल लीग (Tilak's home rule league)

जून 1914 में तिलक 6 वर्ष के कारावास के बाद जेल से रिहा हुए और एक बार पुनः सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे, परंतु इस बार उन्होंने कॉंग्रेस से अलग एनी बेसेंट से मिलकर होमरूल आंदोलन शुरू करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया। एनी बेसेंट कॉंग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन शुरू करना चाहती थीं। अतः अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाँव (पूना) में होमरूल लीग की स्थापना की। तिलक द्वारा स्थापित होमरूल के अध्यक्ष जोसेफ बैपतिस्ता तथा सचिव एन.सी. केलकर थे। इस होमरूल लीग का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र (बंबई को छोड़कर), कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था।

तिलक ने मराठी भाषा में **केसरी** और अंग्रेजी में **मराठा** नामक पत्रों के माध्यम से होमरूल की अवधारणा का प्रचार किया। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण कर स्वराज्य प्राप्ति के लिये जनमत तैयार करने का प्रयास किया।

एनी बेसेंट की होमरूल लीग (Annie Besant's home rule league)

सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी ऑल इंडिया होमरूल लीग की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरंडेल थे तथा बी.पी. वाडिया, सी.पी. रामास्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, वी. चक्रवर्ती तथा जे. बनर्जी जैसे प्रमुख लोकप्रिय नेता इसके सदस्य थे। एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय अडयार (मद्रास) में स्थापित किया गया था। उसने लीग को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। तिलक के कार्य को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में इस लीग की संस्थाएँ सक्रिय

राष्ट्रीय आंदोलन में मज़दूरों एवं महिलाओं की सहभागिता (Participation of Labourers and Women in National Movement)

भारत की स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 ई. में कॉंग्रेस की स्थापना के साथ हुई। आरंभ से ही इस आंदोलन में भारत के बुद्धिजीवियों एवं मध्यम वर्ग का वर्चस्व रहा, जबकि मज़दूरों एवं महिलाओं की सहभागिता शुरुआती दौर में बहुत कम थी। जिस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ ही भारत में मज़दूर संघों की गतिविधियाँ दिखाई देने लगीं, उसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में जब गांधीवादी चरण की शुरुआत हुई तो महिलाओं की सहभागिता इस आंदोलन में दिखने लगी।

12.1 ब्रिटिश भारत में मज़दूर आंदोलन (*Labour movements in British India*)

- ब्रिटिश भारत में मज़दूरों के शोषण, उनकी समस्याओं तथा कारखानों में विद्यमान असुविधाजनक कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार हेतु 1878 ई. में **सोराबजी शपुरजी बंगाली** ने सार्थक प्रयास किया। उन्होंने बंबई विधानसभा में श्रमिकों की कार्याविधि के बारे में विधेयक पेश किया, परंतु वह पारित नहीं हो सका। इससे पूर्व 1870 ई. में बंगाल के शशिपाद बनर्जी ने मज़दूरों के लिये एक क्लब की स्थापना की और **भारत श्रमजीवी** नामक पत्रिका का प्रकाशन किया।
- भारत में गठित प्रथम श्रमिक संघ **बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन** था, जिसकी स्थापना 1890 ई. में **एन.एम. लोखंडे** ने की थी।
- 1897 ई. में स्थायी सदस्यता तथा स्पष्ट नियमों के साथ पहली बार एक मज़दूर संगठन **अमलगमेटेड सोसायटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा** का गठन हुआ।
- भारतीय मज़दूर वर्ग द्वारा प्रथम संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलवे में तब हुई, जब 1899 ई. में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर में कार्यरत श्रमिकों ने कम मज़दूरी और अधिक कार्य अवधि के कारण हड़ताल कर दी।
- 1908 ई. में क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सज़ा होने पर बंबई के कपड़ा मज़दूरों ने लगभग एक सप्ताह की हड़ताल कर दी, जो मज़दूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है।

श्रमिक संघों का गठन (*Formation of labour union*)

- भारत का पहला आधुनिक मज़दूर संगठन **मद्रास मज़दूर संघ** था, जिसकी स्थापना 1918 ई. में बी.पी. वाडिया द्वारा की गई थी।
- मज़दूरों के लिये अखिल भारतीय स्तर का प्रथम संगठन 1920 ई. में एन.एम. जोशी, जोसेफ बैपटिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से **अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (एटक)** के नाम से बनाया गया।
- एटक का प्रथम सम्मेलन 1920 ई. में बंबई में आयोजित किया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष **लाला लाजपत राय** थे।
- कॉन्ग्रेस ने अभी तक मज़दूरों की मांगों एवं अधिकारों को अपने घोषणा-पत्र में शामिल नहीं किया था। सर्वप्रथम 1920 ई. के नागपुर अधिवेशन में श्रमिकों की न्यायोचित मांग तथा उनके संघर्ष के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई।
- लाला लाजपत राय के अतिरिक्त सी.आर. दास, जी.ए. सेन गुप्ता, जी.एफ. एंड्रूज, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं ने भी **अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (एटक)** की अध्यक्षता की थी।
- ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था- 1926 से 1939 तक।

नोट: 'New lamps for old' लेख शृंखला (1893-94) में सर्वहारा-वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिये कॉन्ग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों को लिखने वाले लेखक अरविन्द घोष थे।

गणतंत्र के रूप में भारत का उदय (Rise of India in the Form of a Republic)

गणतंत्र के रूप में राष्ट्र निर्माताओं ने भारत की विविधता को एक समस्या के रूप में न देखते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस विविधता को एक शक्ति का स्रोत माना। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अधिक एवं जटिल सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाला देश है। अतः गणतंत्र के रूप में भारत का निर्माण विविधता में एकता की अवधारणा के साथ हुआ। हालाँकि, एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण में अनेक जटिलताएँ भी मौजूद थीं, परंतु स्वतंत्रता उपरांत भारतीय राष्ट्र का निर्माण एक वृहद् रणनीति के तहत किया गया। इस रणनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष संविधान था, जिसमें समस्त नागरिकों को धर्म, जाति व लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त कर, समाज के हर वर्ग को पूरी समानता देने की बात कही गई। आरक्षण तथा प्रतिबद्धता के माध्यम से भारतीय संविधान ने वंचित वर्गों के हितों को पुष्ट करने का प्रयास किया। इस संविधान को 26 जनवरी, 1950 को पूर्णरूपेण लागू करने के साथ ही भारत का उदय गणतंत्र के रूप में हुआ।

13.1 राज्यों का पुनर्गठन (Reorganization of States)

भाषा व संस्कृति का गहरा संबंध होता है तथा इसका असर जनता के रीति-रिवाजों पर भी पड़ता है। वैसे भी हिंदुस्तान विविधताओं से भरा देश है, जहाँ कई प्रकार की भाषाएँ, विभिन्न लिपियाँ, व्याकरण, शब्द-भंडार व साहित्यिक परंपराएँ पहले से ही विद्यमान हैं।

राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने सर्वप्रथम 1917 ई. में ही स्वतंत्रता के बाद होने वाले राज्यों के गठन को भाषायी आधार पर करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। 1920 ई. में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बाद भाषायी आधार पर ही कांग्रेस प्रदेश समितियों का गठन हुआ था। उपरोक्त आधारों पर भाषायी गठन के सिद्धांत को बढ़ावा मिला। भाषा के आधार पर कांग्रेस की उपसमितियों को संगठित करने के निर्णय का गांधीजी ने भी स्वागत किया था। स्वतंत्रता के बाद नए भारत में प्रांतों का गठन भाषायी आधार पर करने का समर्थन गांधी, नेहरू, पटेल व अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा भी किया गया था।

परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश के सामने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जटिलताएँ समस्या बनकर खड़ी हो गईं, क्योंकि ब्रिटिश भारत में भारतीय प्रदेशों की जो सीमाएँ बनाई गई थीं, वे ब्रिटिश हितों के अनुरूप व अतार्किक थीं। इन प्रदेशों की सीमाओं का निर्धारण करते समय ब्रिटेन द्वारा भाषा व संस्कृति की समरूपता का ध्यान नहीं रखा गया था।

अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाने के बाद प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए मनमाने तरीके से भारत को नए सिरे से बड़े-बड़े प्रांतों में बाँट दिया, एक भाषा बोलने वालों की भू-क्षेत्रीय समरसता पूरी तरह से भंग कर दी गई। बहुभाषी व बहुजातीय प्रांत बनाए गए। अतः इस विषमता को समाप्त करने हेतु कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने स्वतंत्रता उपरांत भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विचार बनाया, परंतु देश के विभाजन के बाद धार्मिक आधार पर लोगों में दूरियाँ बढ़ने के कारण भाषायी आधार पर एक नई दूरी पैदा करने के पक्ष में पं. नेहरू, सरदार पटेल, सी. राजगोपालाचारी सहित कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब नहीं था। अतः सर्वप्रथम संविधान सभा ने एस.के. धर के नेतृत्व में धर आयोग का गठन किया, जिसने भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग ठुकरा दी।

धर आयोग

भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जाँच के लिये संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में 1948 ई. में चार सदस्यीय एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता को खतरा एवं प्रशासन को भारी असुविधा का तर्क देकर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया।

संविधान सभा के इस प्रयास से जन-भावनाएँ संतुष्ट न होकर और भड़क गईं, विशेष तौर पर दक्षिण भारत सबसे अधिक असंतुष्ट रहा। वहाँ इस समस्या ने राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया। अतः कांग्रेस ने इस समस्या को समाप्त करने हेतु

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का एक राष्ट्र के रूप में उभरना अचानक घटित होने वाली घटना न होकर एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था। भारतीय सभ्यता में विविधता के लक्षणों को हम प्राचीन काल से ही देख सकते हैं। जैसा कि कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने भी माना है कि “भारत की एकता भावनाओं की एकता है।” स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीयों को राजनीतिक व भावनात्मक रूप से जोड़ दिया था, साथ ही भारत को एक राष्ट्र का स्वरूप दे दिया था। लेकिन अभी भी भारत को पूरी तरह से राष्ट्र नहीं कहा जा सकता था, बल्कि यह राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में ही था। चूँकि भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया दीर्घकालीन व सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया थी।

वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले नेतागण, (पटेल, नेहरू, मेनन आदि) जो विभिन्न क्षेत्र, भाषा व धर्म से संबंधित थे, फिर भी जब इस नए गणतंत्र की बुनियाद रख रहे थे तो उन्होंने भारत के एकीकरण और राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को न सिर्फ बनाए रखना चाहा बल्कि उसे भविष्य में और अधिक विकसित करने के बारे में भी सोचा।

14.1 राष्ट्र का विभाजन (Partition of Nation)

15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा तथा राष्ट्र को संबोधित करते हुए ‘ट्रिस्ट विद डेस्टिनी’ नामक अपने अविस्मरणीय भाषण में भारतीय जनता की भावनाओं को व्यक्त किया। देश अब आजाद हो चुका था। अपने सपनों को साकार करने का समय आ गया था।

स्वतंत्र भारत का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। आजादी की कीमत देश के विभाजन से चुकानी पड़ी। कठिन परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करते हुए भारत को विकास का रास्ता तय करना था।

विभाजन

‘ये दाग-दाग उजाला, ये शब-गजीदा सहर
वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं’

मशहूर शायर फैज अहमद फैज की ये पंक्तियाँ विभाजन की पीड़ा को बड़े ही गंभीर शब्दों में बयान करती हैं। 1940 के बाद उपजी राजनीतिक परिस्थितियों के बीच मुस्लिम लीग के ‘द्वि राष्ट्र सिद्धांत’ को मान लिया गया। इंडिया के नाम से चिह्नित भू-भाग को ‘भारत’ और ‘पाकिस्तान’ नाम के देशों में बाँट दिया गया। यह विभाजन दर्दनाक था और इसे वास्तविकता देना और भी कठिन था। धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया गया, लेकिन 14-15 अगस्त, 1947 की आधी रात तक यह फैसला नहीं हो पाया था कि पंजाब और बंगाल के कौन-से इलाके पाकिस्तान और कौन-से भारत में हैं। पंजाब और बंगाल का बँटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी थी।

बड़े पैमाने पर आबादी का स्थानांतरण हुआ, जो कि मानव-इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। धर्म के नाम पर लोगों ने एक-दूसरे को मारा। लोग अपना घर-बार, कारोबार और ज़मीन छोड़ने पर मजबूर हुए। महीनों, सालों तक उन्हें शरणार्थियों के रूप में शिविरों में जीवन बिताना पड़ा। कल तक लोगों का जो अपना वतन था, आज वहीं वे बेगाने थे।

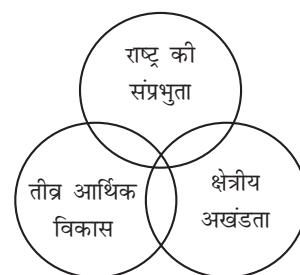
महात्मा गांधी बँटवारे के समय सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिये कलकत्ता में थे। उनके प्रयासों से हिंसा में काफी कमी आई, इसीलिये लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें ‘वन मैन आर्मी’ कहा था। लेकिन गांधी जी को इसकी कीमत अपनी शहादत से चुकानी पड़ी। एक हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी, 1948 को गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के दौरान उन्हें गोली मार दी। गांधी जी की मौत का प्रभाव बहुत चमत्कारी था। विभाजन से जुड़ी क्रोध और हिंसा धीरे-धीरे मंद पड़ गई।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति (Indian Foreign Policy in Global Perspective)

भारत की विदेश नीति के मूलभूत तत्त्व राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही निर्मित होने शुरू हो गए थे, जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी विचारधारा के अनुसार नीतियाँ बनानी शुरू कर दी थीं। एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने का प्रयत्न आज़ादी के बाद की भारतीय राजनीति की विशेषता थी। भारतीय विदेश नीति लंबे इतिहास और हाल की घटनाओं की परिणति थी। विश्व परिस्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तनों के बावजूद आज़ादी के संघर्ष और आज़ादी के आरंभिक वर्षों में विकसित विशेषताओं की निरंतरता बाद के वर्षों में भी बनी रही। भारतीय विदेश नीति के मुख्य शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्रता के बाद से मृत्युपर्यन्त तक भारतीय विदेश नीति इनके वृहद् मानवतावादी व्यक्तित्व तथा सिद्धांतों के आस-पास ही घूमती रही। अपनी विदेश नीति के तहत भारत सिर्फ निष्पक्ष या सैनिक गुटों से दूर ही नहीं रहा बल्कि इसने अपनी आवश्यकतानुसार तत्कालीन महाशक्तियों का उपयोग भी देशहित में किया। भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का अर्थ था—हर मुद्दे पर आज़ादी से रुख अपनाना, सही या गलत की स्वयं पहचान करना।

15.1 भारत की विदेश नीति और पंचशील समझौता (India's Foreign Policy and Panchsheel Agreement)

भारत सन् 1947 में स्वाधीन हुआ और इसके सामने दुनिया में अपनी छवि विकसित करने और उस काल की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित करने जैसी चुनौतियाँ थीं। भारत की विदेश नीति पर स्वाधीन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गहरी छाप थी। उन्होंने इसको पाला-पोसा था, जीवन और शक्ति प्रदान की थी और अनेकानेक उपायों से इसे आकार दिया था, लेकिन उन्होंने इसे गढ़ा नहीं था। नेहरू ने खुद ही स्वीकार किया था कि भारत की विदेश नीति की जड़ें भारत की सभ्यता और परंपराओं में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, इसकी भौगोलिक स्थिति में और शांति-सुरक्षा, विकास तथा इस जगत् में एक स्थान के लिये भारत की तलाश में स्थित थी। उन्हीं के शब्दों में, “हमारी नीति को ‘नेहरू नीति’ कहना बिल्कुल गलत है...इसे मैंने जन्म नहीं दिया। यह नीति भारत की परिस्थिति में, भारत के अतीत की सोच में, भारत के संपूर्ण दृष्टिकोण में निहित है, यह निहित है भारतीय मानस के उस अनुकूलन में जो स्वाधीनता संग्राम के दौरान हुआ था और यह आज की दुनिया के हालात में निहित है।” नेहरू पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता था कि विदेश नीति के मामले में वह आदर्शवादी और नैतिकतावादी हैं। दरअसल वह इनमें से कोई नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के हितों या इसकी संप्रभुता का बलिदान किये बगैर उन्होंने देश को शीतयुद्ध के बारूदी सुरंगों भरे क्षेत्र के बीच चलाने में भारी यथार्थवाद को प्रदर्शित किया था। लोग उन हालातों, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों को भूल जाते हैं, जिनमें नेहरू ने भारत की विदेश नीति को स्वरूप दिया था।



प्रारंभिक विदेश नीति

सन् 1947 में जब स्वाधीनता प्राप्त हुई, भारत के पास नाममात्र की सैनिक और आर्थिक शक्ति थी। विभाजन सेना में भी हुआ था और इसका एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया था। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का संबंध है, इसके लिये आलोचनापूर्वक यह कहा जाता था कि भारत में तब एक पिन भी नहीं बनती थी। नेहरू का मानना था कि अपने मुट्ठी भर संसाधनों का इस्तेमाल प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक विकास के लिये निवेश करने में करना चाहिये अथवा सैनिक तैयारियों के लिये करना चाहिये। जो सैनिक शक्ति मजबूत आर्थिक नींव पर आधारित नहीं, वह स्थायी नहीं होगी, वह बालू पर बनाई गई नींव जितनी क्षणिक होगी। अनेक देशों के उदाहरण सामने थे, जैसे कि उस काल का पाकिस्तान और थाईलैण्ड, जिन्होंने मूलतया सैनिक शक्ति पर भरोसा किया था, जिसे उनकी अर्थव्यवस्था का समर्थन प्राप्त नहीं था। इन पर सदा अस्थिर शासकों का राज रहा और वे लगातार दूसरे देशों पर निर्भर रहे थे। नेहरू अत्यंत यथार्थवादी थे। वे जानते थे कि देश का स्थायित्व और इसका सामाजिक सामंजस्य इसकी आर्थिक शक्ति पर टिका होता है। उनकी समझ थी कि वह प्रत्येक पैसा जो वे आर्थिक

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com



DrishtiIAS



YouTube Drishti IAS



drishtiias



drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456